आरएसएस की सत्ता के खिलाफ व्यापक वाम मोर्चा वक्त की ज़रूरत

- दिव्यांग

नरेंद्र मोदी (आरएसएस) सरकार के दो वर्ष पूरे हो गए। अब तीन वर्ष और बाकी हैं। ये तीन वर्ष कैसे बीतेंगे और इस दौरान मोदी सरकार क्या-क्या कहर बरपाएगी, यह सोच कर लोग परेशान हैं। चंद आरएसएस समर्थकों को छोड़ कर प्रायः लोगों का यही मानना है कि यह सरकार कांग्रेसी नेतृत्व वाली सरकार से भी कई गुना खराब है और इसका सत्ता में आना बहुत बुरा साबित हुआ है। पर अब कर क्या सकते हैं रोने के सिवा। मोदी ने अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया। उलटे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को बेलगाम छोड़ दिया, जिसका खामियाजा लोगों को लगातार बढ़ती महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। मोदी सरकार की हर नीति दिवालिया है। अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक यह कांग्रेस की नीतियों को ही लागू कर रही है, पर और भी भद्दे तरीके से। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को बाजार के हवाले किया, पर उसकी गति धीमी थी। राजीव गांधी से शुरू हुई यह प्रक्रिया नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के शासन के दौरान परवान चढ़ी, लेकिन मोदी जी की खासियत ये है कि इन्होंने अपनी सरकार को ही बाजार के हवाले कर दिया। इनकी सरकार अंबानी-अडानी चला रहा है। कांग्रेसी योजनाओं को नया नाम देकर मोदी उसे अपनी उपलब्धि बताते हैं, पर जनता यह समझ रही है कि यह तो कांग्रेसियों से भी बड़ा लुटेरा निकला। दूसरे, इसने सामाजिक शांति भी भंग की है। भाजपा का अध्यक्ष अमित शाह जो एक दंगाई और तड़ीपार है, हमेशा उन मुद्दों की तलाश में रहता है, जिनसे धार्मिक विद्वेष पैदा हो और दंगे भड़काए जा सकें। दंगे भड़काने में और सुनियोजित कत्लेआम करवाने में मोदी-अमित शाह की जोड़ी को महारत हासिल है। ऐसे न जाने कितने सबूत हैं जो दिखाते हैं कि गुजरात दंगे भड़काने और हजारों लोगों की हत्या करवाने में इन दोनों की भूमिका रही है, पर इसने न्यायपालिका को अपने पक्ष में कर क्लीन चिट ले लिया।

यह वास्तव में इस देश का दुर्भाग्य है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक दंगाई और मूर्ख व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। मोदी की मूर्खताओं पर न जाने कितने चुटकुले बन चुके हैं। इस आदमी को उतनी जानकारी भी नहीं है, जितनी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को होती है। देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति आदि के ज्ञान से शून्य यह व्यक्ति दुनिया भर में अपनी भद्द पिटवाता रहता है।

बहरहाल, जनता के लिए इसने बड़ी विकट स्थिति पैदा कर दी है, जो महंगाई की मार से मरी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा भी पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। अब सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा? अगर आरएसएस सत्ता में आने में सफल हुआ तो इसके पीछे वजह ये रही कि जनता कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से बेतरह परेशान थी और उसने बदलाव का मन बना लिया था। पर बदलाव पहले से भी बुरा होगा, ये कुछ लोग ही समझ रहे थे जो आरएसएस के चरित्र से परिचित थे। किसी विकल्प के अभाव में और झूठे प्रचार के बल पर आरएसएस सत्ता में आ गया। 'अच्छे दिन' का नारा देकर प्रधानमंत्री बने मोदी ऐसे दुर्दिन लेकर आए कि अब आम जनता को न रोते बन पड़ रहा है, न हंसते। 'अच्छे दिन' आए महज अंबानी-अडानी और दस प्रतिशत लोगों के जो इन पूंजीपतियों के दलाल हैं या उच्च वर्ग में शामिल हैं। मोदी की एक खासियत ये भी रही कि इन्होंने प्रचार तंत्र यानी मीडिया पर कब्ज़ा कर लिया। यह काम इन्होंने मीडिया को खरीद कर ही किया। कांग्रेस का संभवत: यह एजेंडा नहीं रहा, वर्ना मीडिया को वह भी खरीद सकती थी। बहरहाल, जनता बदलाव चाहती थी तो उसे बदलाव मिला, लेकिन बदतर। अब सवाल ये है कि ये मोदी (आरएसएस) सरकार से देश को छुटकारा कैसे मिलेगा? इस बात में दो रया नहीं कि यह सरकार पांच साल तक तो रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या ? यह ऐसा सवाल है जो हर विचारशील व्यक्ति के मन में है। दो साल तो जनता ने झेल लिया, तीन साल और झेल लेगी, यह और बात है कि तब तक यह सरकार देश के संसाधनों को पता नहीं कितना लूटेगी और लुटवाएगी, लेकिन 2019 में जब आम चुनाव होंगे तो क्या होगा ? कैसा विकल्प सामने आएगा, यह एक गंभीर प्रश्न है। यहां देश के प्रमुख राजनीतिक दलों की स्थिति पर विचार करना जरूरी होगा। भाजपा के बरक्स कांग्रेस अभी भी एक सबसे बड़ी पार्टी है। अन्य दल क्षेत्रीय चरित्र वाले हैं, यद्यपि अखिल भारतीय राजनीति में उनका महत्व कम नहीं है। वामपंथी दल भी अलग स्थान रखते हैं। लेकिन इन दलों की फिलहाल कोई ऐसी नीति या कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जिनके आधार पर कहा जाए कि वे आने वाले समय में भाजपा-आरएसएस के लिए चुनौती बन सकेंगे।

लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सत्ता में आने के बाद अब राज्यों में भाजपा को यद्यपि कोई बड़ी जीत मिलती नहीं दिख रही, पर कांग्रेस की स्थिति भी पहले से कमजोर होती जा रही है। झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में भाजपा शासन हर मोर्चे पर फेल है और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। वहां नये समीकरण बन सकते हैं जो भाजपा के खिलाफ जाएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। व्यापमं घोटाले ने शिवराज की कलई खोल दी है। यहां भी जब चुनाव होंगे, शिवराज का फिर से सत्ता में लौट पाना मुश्किल होगा। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को हटाने की कोशिश मोदी जी को भारी पड़ी है और इससे भाजपा की कलई खुली है। पर जो बेशर्मी की हद पर उतरा हो, उसे इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब कि भाजपा में वो दम नहीं कि अगले चुनाव में वह जीतने की उम्मीद कर सके। अभी हुए विधानसभा चुनावों में सिर्फ असम में उसे जीत मिली है, यह उसकी उपलब्धि मानी जाएगी, साथ ही कांग्रेस के एक किले का ढहना।

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम वामपंथी दलों को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। ममता बनर्जी का वहां पहले से भी मजबूत हो कर उभरना यह दिखा देता है कि वामपंथियों की दाल वहां अभी गलने वाली नहीं है और कांग्रेस के साथ उनके गठबन्धन का कोई भविष्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो यह साबित हो ही चुका है, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी साबित हो जाएगा। दरअसल, वामपंथियों को अपने संगठन और कार्यनीति पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। भूलना नहीं होगा कि देश में मज़दूरों-किसानों की एक बड़ी आबादी के साथ मध्य वर्ग का एक ऐसा तबका भी है जो इनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। लेकिन ये पूंजीवादी राजनीति के घेरे से निकल पाने को तैयार नहीं दिखते। जबकि अभी भी इनका सांगठनिक ढांचा इतना मजबूत जरूर है कि ये चाहें तो एक बड़ा अभियान चला कर विकल्प की राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें अपनी सीमाओं से निकलना होगा और सुविधाभोगी संस्कृति से पीछा छुड़ाना होगा। वामपंथियों में अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, बावजूद इनका कन्हैया जैसे अनुभवहीन युवा पर निर्भर हो जाना इनकी कमजोरी को ही दिखलाता है। कन्हैया का प्रयोग असफल रहा, यह वामपंथियों को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने आधार की तलाश विश्वविद्यालयों से अलग हट कर फैक्ट्रियों और कामगार आबादी केबीच करनी चाहिए। निश्चय ही, इससे इन्हें नई ऊर्जा मिलेगी और ये जनविकल्प खड़ा करने की दिशा में कुछ कर सकेंगे। इसी आधार पर इन्हें वाम दलों के बीच एकता भी स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हें यह समझना चाहिए कि देश फासीवाद की चुनौती से जूझ रहा है और ऐसे में अब पुराने खोल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कांग्रेस एवं अन्य सत्तालोलुप दलों के पीछे चल कर वामपंथी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपनी खोती जा रही जमीन को पूरी तरह खो देंगे। इसलिए आरएसएस की सत्ता के खिलाफ इन्हें एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए और अपने संगठनों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी हड़ताल और आंदोलनों की शुरुआत करनी चाहिए। तभी कोई रास्ता खुल सकता है। सोनिया, लालू, नीतीश और इस तरह के नेताओं के पीछे चलने से आरएसएस की सत्ता का कोई जनविकल्प सामने नहीं आ सकता। हां, आरएसएस के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष में जो दल इनसे जुड़ना चाहें, उन्हें अपने साथ ये ले सकते हैं। आज जो स्थितियां बन गई हैं, उनमें वर्तमान फासीवादी सत्ता के खिलाफ एक व्यापक वाम मोर्चा की राजनीति ही कारगर हो सकती है।

एप्पल के काम कराने का तौर-तरीका

एप्पल कम्पनी आई पैड, आई फ़ोन और कम्प्यूटर बेचती है। साथ ही यह इन उपकरणों की डिजाइन, मार्केटिंग और प्रबन्धन को भी देखती है। इसने 2011, 2012 और 2013 में क्रमशः 108, 156 और 170 अरब डॉलर की बिक्री की। करोड़ों आई पैड बेचनेवाली इस कम्पनी की अपनी कोई उत्पादन इकाई नहीं है। एप्पल की प्रबन्धन टीम उत्पादों के निर्माण के लिये मुख्यतः एशिया में ठेकेदारों की एक पूरी श्रृंखला को सम्भाले हुए है। इसके प्रबन्धनों ने दुनिया-भर में ठेकेदारों का चयन इस तरह किया है कि उत्पादन में श्रम की लागत को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एप्पल के कुल 748 ठेकेदारों में से 82 फीसदी एशिया में हैं। उनमें से 351 तो अकेले चीन में है। कोई इस धोखे में रह सकता है कि आज पूरब इतना उन्नत हो गया है कि पश्चिम के लिए उत्पादन कर रहा है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज भी यूरोपीय और अमरीकी कम्पनियों की गिद्ध दृष्टि तीसरी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों और सस्ते श्रम पर लगी हुई है। किसी भी तिकड़म से वे इन्हें हासिल करना चाहती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का मुख्य लक्षण है ''अधिक से अधिक मुनाफ़ा''। किसी भी कीमत पर। देशों को गुलाम बनाकर, अफ़ीम बेचकर, हथियार और बम बेचकर या सेक्स सीडी का कारोबार करके। पूंजीवाद के इन्हीं काले अध्यायों में एप्पल जैसी दिग्गज कम्पनियां राजनीतिक गठजोड़ करके सस्ते श्रम और सार्वजनिक संसाधनों की लूट के नये अध्याय जोड़ रही हैं। 21 वीं सदी में पूंजीवाद पुराने तरीके से उपनिवेश और राष्ट्रों के गुलाम बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पूंजीवाद अपनी लूट-खसोट की मंशा पर कायम है, आज उसने तीसरी दुनिया के देशों के संसाधनों की लूट और श्रम के शोषण का तरीका बदल लिया है।

एप्पल कम्पनी उपकरणों का उत्पादन जिन स्थानीय ठेकेदारों के यहां करा रही है वहां श्रम के शोषण और अमानवीय परिस्थितियों का अन्दाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एप्पल का ठेका लेने वाली चीन की फोक्सकोन फैक्ट्री में 18 से 25 साल की उम्र वाले 18 मज़दूरों ने पिछले दिनों आत्महत्या का प्रयास किया। जिनमें से 14 की जीवन लीला समाप्त हो गयी बाकी जीवन-भर के लिए अपंग हो गये। एप्पल ने जिन देशों में कारोबार किया है, वहां तरह-तरह की रणनीति अपनाकर केवल 2-3 प्रतिशत टैक्स चुकाया जबकि आयरलैंड में उसने कोई टैक्स जमा ही नहीं किया है। दूसरी तरफ़, एप्पल के लिये 12 से 14 घंटे बुरी हालत में काम करने के बावजूद मज़दूरों को न्यूनतम वेतन से भी कम मज़दूरी दी गयी। 2010-11 में एक आई पैड की कीमत 499 डालर थी जबकि फैक्ट्री लागत 275 डॉलर। इस 275 डॉलर में से उत्पादन में लगे लोगों को बमुश्किल 33 डॉलर मिला। 150 डॉलर डिजाइन, मार्केटिंग और प्रबन्धन में लगे लोगों की तनख्वाहों पर खर्च हुए, बाकी ठेकेदारों का कमीशन और अन्य खर्चों में। अब मान लीजिए यही आई पैड अमरीका में तैयार होता तो उत्पादन में खर्च 33 डॉलर नहीं 442 डॉलर आता। अगर हम थोड़ा और गहराई से जायें और कहें कि आई पैड के अन्दर के छोटे-छोटे पुर्जे भी अमरिका में ही बनाये जाते तो इनकी कीमत 210 डॉलर प्रति आई पैड होती जबकि दक्षिणी देशों और एशिया में ये पुर्जे महज 35 डॉलर प्रति आई पैड में बनते हैं। यही वह मुनाफ़ा है जो इन दैत्यकार कम्पनियों को हमारे जैसे देशों में आने को ललचा रहा है।

कितना हास्यास्पद है कि भारत और तीसरी दुनिया के तमाम अन्य देश जो साम्राज्यवादी लूट-खसोट के चलते आर्थिक रूप से पिछड़ गये थे, आज उन्हीं साम्राज्यवादियों के साथ सांठ-गांठ करके अपनी आर्थिक समृद्धि तलाश रहे हैं। उनके साथ सम्बन्धों और गठजोड़ों को इस कदर जरूरी बताया जा रहा है, जैसे कोलम्बस ने अमरीका की खेज न की होती तो आज भारत के सामने विकास का रास्ता ही न होता। करोड़ों मेहनतकश नौजवान, पर्याप्त खनिज संसाधन, उपजाऊ जमीन, मौसम में विविधता और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण देश अपनी आर्थिक सम्पन्नता और बुनियादी समस्याओं का हल विश्व बैंक और विदेशी निवेशकों में ढूंढ रहा है। यह भारतीय शासक वर्ग की नीतियों की नाकामी ही है कि उसने पूंजीपति वर्ग के संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए जनहित में कोई दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बनायी और अब तो पूरी तरह देशी-विदेशी पूंजी का चाकर बना हुआ है।

हमारे देश के शासक वर्ग ने बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये अनुकूल परिस्थितियां तैयार की हैं। मौजूदा सरकार श्रम कानूनों से फेरबदल करके रही-सही कमी पूरी करने में लगी है। एक बहुराष्ट्रीय निगम को और क्या चाहिए? बेरोजगारों की भीड़, खेती को घाटे का सौदा माननेवाले हताश-निराश किसान, लचर श्रम कानून और पूंजी की रक्षा करनेवाले शासक।

हमारा दुर्भाग्य! इन सहिष्णु और देशभक्त शासकों ने भारत में सारी अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दी हैं। बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में दुनिया-भर की अर्थव्यवस्थाओं का विध्वंश करनेवाले इस बिना नाथ-पगहा के जानवर को मेहनतकश जनता का सामूहिक प्रयास ही काबू में ला सकता है। जिसे देर-सवेर होना ही है।

-राजेश चौधरी

एक शातिर अपराधी की तरह काम करता है जी न्यूज एंकर सुधीर चौधरी

कहते हैं काठ की हांडी एक बार चढ़ती है; समय ऐसा है कि दुबारा भी चढ़ जाती है!

गंदा काम ज़ी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी ने जेएनयू के मामले में ही नहीं किया; उन्होंने अन्य चैनल में भी ऐसा कुकर्म किया था। तब भी वे चैनल (लाइव इंडिया) के प्रमुख थे। उनके एक योजनाबद्ध प्रसारण (अगस्त 2007) की बदौलत एक निर्दोष शिक्षिका बेतरह बदनाम हो गई। प्रसारण में शिक्षिका पर अपने स्कूल में छात्राओं का सैक्स रैकेट चलाने का फरजी स्टिंग मढ़ा गया और धुंधलाए %स्टिंग% को बार-बार दिखाया गया। इतना कि समाज भड़क उठा, तोड़-फोड़ और आगज़नी हुई, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने शिक्षिका को घेरकर सरेआम पीटा, कपड़े फाड़ दिए, बाल पकड़ कर घसीटा, इतना मारा कि महिला की जान जाते-जाते बची।

पर टीवी की शिकार उस शिक्षिका को न्यायालय ने न्याय दिया। न्यायाधीश ने कहा कि शिक्षिका अपराधी नहीं हैं, अपराधियों की करतूत की शिकार हुई लगती हैं।

चैनल के कुकर्म की पोल अंततः खुल गई। स्टिंग फरजी निकला, स्टिंग की छात्रा एक रिपोर्टर निकली! सरकार ने चैनल को बैन कर दिया। सुधीर और उनके साथी पत्रकार बदनाम हुए, सड़क पर आ गए। उन्हीं सुधीर चौधरी ने जेएनयू के एक आयोजन को अपने चैनल पर इस तरह पेश किया जैसे देश में सीधे राष्ट्रवाद पर हमला हो गया; देखते-देखते छद्म राष्ट्रवादियों में उन्माद पनप गया, सीधे सरकार ने जेएनयू को ललकारा, गृहमंत्री बोले, पुलिस प्रमुख के निर्देश पर पुलिस परिसर में जा धमकी, छात्र गिरफ्तार हुए, अदालत में पुलिस के घेरे में छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके समर्थकों पर हिंसक हमला हुआ। फर्क इतना ही है कि इस दफा कुछ और चैनल भी उस कदमताल में शरीक पाए गए। सरकार की जाँच में तीन वीडियो क्लिप हेराफेरी वाले निकले, मजिस्ट्रेट की जाँच में और ही तथ्य दरपेश आए - और सरकार और न्यायालय कथित राष्ट्रप्रेम के झूले में एक साथ झूलते नजर आए। और सुधीर चौधरी मोदी सरकार द्वारा अता फरमाई गई एक्स-कैटगरी की सुरक्षा व्यवस्था ओढ़कर अपने रास्ते पर अपनी शान में आगे बढ़े जाते हैं - सौ करोड़ की रिश्वत के आरोप में जेल की हवा खा आने के बाद!

सुधीर चौधरी आज मोदी सरकार की आँख के तारे हैं, प्रधानमंत्री उनसे सीधे बात करते हैं (अभी पिछले हफ्ते चौधरी ने मोदी की रिटर्न कॉल का ब्योरा चैनल पर पेश कर अपना रुतबा बढ़ाया है!) कुछ के लिए सही, पर कौन कहता है ये अच्छे दिन नहीं?

- ओम थानवी